सत्यमेव जयते

बिहार विधान परिषद्

191 वां सत्र

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

वर्ग – 4

25 माघ, 1940 (श.)

वृहस्पतिवार तिथि -------------------------------------

14 फरवरी, 2019 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 22

1.	गृह (आरक्षी) विभाग	---	---	05
2.	लघु जल संसाधन विभाग	---	---	03
3.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	---	---	04
4.	योजना एवं विकास विभाग	---	---	01
5.	समाज कल्याण विभाग	---	---	04
6.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	---	---	01
7.	वित्त विभाग	---	---	02
8.	श्रम संसाधन विभाग	---	---	01
9.	गृह (विशेष) विभाग	---	---	01

		कुल योग -		22

राशि का वितरण

49. प्रो. नवल किशोर यादव : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर में वर्ष 1989-90 में दंगा पीडितों के आश्रितों को अतिरिक्त सहायता के लिए केन्द्र से मिली रकम में से 72 लाख रुपये विभाग द्वारा जिलाधिकारी, भागलपुर को दिया जा चुका है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त भेजी गई राशि का वितरण अभी तक उन आश्रितों के बीच नहीं किया जा सका है ;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार दंगा पीडितों के आश्रितों को इंगित कर उनके बीच राशि का वितरण करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक ?

.....

नलकूप चालू कबतक

50. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के खुसरूपुर प्रखण्ड स्थित सालिमपुर ग्राम में दो राजकीय नलकूप लगा हुआ है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त दोनों राजकीय नलकूप वर्षों से बंद पड़ा हुआ है जिससे किसानों को सिंचाई करने में काफी परेशानी हो रही है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र उक्त दोनों नलकूपों को चालू कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

.....

पार्क का निर्माण

51. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिला के थावे में विगत कई वर्ष पूर्व एक पार्क निर्माण हेतु भूमि भी चयनित हो चुकी है एवं पार्क के शीघ्र निर्माण हेतु विभागीय कार्रवाई चल रही है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थल पर पार्क निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा चयनित भूमि संबंधित अभिलेख विभाग को समर्पित कर दी गयी है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या राज्य सरकार गोपालगंज के थावे में पार्क का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

.....

राशि का ब्यौरा

52. **श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत जिलों में उपलब्ध अद्यतन राशि की सूचना माननीय विधान मंडल के सदस्यों को जिला योजना पदाधिकारी द्वारा नहीं दिया जाता है जिसके कारण योजना एवं उसकी लागत का सही आकलन नहीं हो पाता है ;

(ख) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व लगभग दिसम्बर-जनवरी माह में शेष सारी राशि का ब्योरा माननीय विधायक / विधान पार्षदों को पत्र / मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

.....

बकाया राशि कबतक

53. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत बी.पी.एल. परिवार के व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी अंत्येष्टि के लिए परिवार को तीन हजार रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है ;

(ख) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य में कई आवेदन प्राप्त हुए हैं, कितने लोगों को राशि दी गयी है, और कितने लोगों को अभी राशि देनी है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कबीर अंत्येष्टि योजना के अन्तर्गत बकाया राशि को कबतक देना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

उतर –

(क) स्वीकारात्मक है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2018 19 में कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजनान्तर्गत राज्य में अभी भी कुल 43,035 (तैतालीस हजार पैंतीस) आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 40,096 (चालीस हजार छियानवें) लाभुकों को भुगतान किया जा चुका है। शेष 2,939 (दो हजार नौ सौ उन्चालिस) लाभार्थियों का भुगतान प्रक्रियाधीन है।

(ग) अंश 'ख' में स्थिति स्वत: स्पष्ट कर दी गई है।

.....

नियुक्ति कबतक

54. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के 38 जिलों में 23041 नये आंगनबाड़ी केन्द्र और 1675 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गए हैं, जिससे करीब एक करोड़ लोगों को फायदा मिल सकेगा ;

(ख) क्या यह सही है कि स्थायी तौर पर कामकाज के लिए फिलहाल 10 हजार सेविकाओं और सहायिकाओं की नियुक्ति हो चुकी है, लगभग 34 हजार की नियुक्ति होनी बाकी है ;

(ग) क्या यह सही है कि सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सेविकाओं और सहायिकाओं की नियुक्ति हो जाने से खासकर महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य लाभ और पोषण संबंधी शुरुआती जरूरतों की पूर्ति हो सकेगी ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 34 हजार सेविकाओं और सहायिकाओं की नियुक्ति कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

उत्तर –

(क) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार द्वारा कुल 23041 नये आंगनबाडी केन्द्रों की वार्डवार स्वीकृति दी गई है। निदेशालय के पत्रांक 1159 दिनांक 27.3.17 द्वारा 21366 सामान्य आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 1675 मिनी आंगनबाडी केन्द्र खोले गए हैं। उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से उनके पोषक क्षेत्र में

0-6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं सहित किशोरी बालिकाओं को आंगनबाडी केन्द्रों पर दी जानेवाली सेवाओं से लाभान्वित किया जाता है।

(ख) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में सेविकाओं के कुल 114718 आंगनबाड़ी सेविका के पद स्वीकृत हैं जिनमें सामान्य केन्द्र 107603 एवं मिनी केन्द्र पर 7115 सेविका के पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत पद के विरूद्ध सामान्य आंगनबाडी केन्द्र पर 91210 सेविका एवं 5057 मिनी सेविका कार्यरत हैं। 18451 सेविका एवं 20017 सहायिका का चयन बाकी है। जिसपर चयन प्रक्रियाधीन है। चयन एवं रिक्ति एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) स्वीकारात्मक है।
आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जानेवाली सेवाओं स्कूल पूर्व शिक्षा, पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा संदर्भ सेवाओं से महिलाओं एवं बच्चों को लाभान्वित किया जाता है। इसके साथ ही सरकार की अन्य योजनाओं यथा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आदि योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

(घ) उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। रिक्त केन्द्रों पर चयन की कार्रवाई की जा रही है। जिसे निकट भविष्य में पूरा कर लिया जाएगा।

.....

छात्रवृत्ति की राशि

55. **श्री मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी योजना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है जिसमें राज्य के छात्रों को IIT, NIT में अध्ययन हेतु भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ;

(ख) क्या यह सही है कि इसी छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत NIT, जयपुर (वर्ष 2015) के छात्र श्री राहुल कुमार को वित्तीय वर्ष- 2016 में छात्रवृत्ति प्रदान की गई ;

(ग) क्या यह सही है कि श्री कुमार को (आवेदन सं0-PMO1161700698082) सत्र 2016-17 की छात्रवृत्ति बारंबार कल्याण पदाधिकारी, पटना से मिलने एवं अनुरोध करने के बावजूद रिश्वत नहीं दिये जाने के कारण मीटिंग नहीं होने का बहाना बनाकर नहीं दी जा रही है, जबकि राज्य के दूसरे जिलों में छात्रवृत्ति की राशि काफी पहले ही निर्गत की जा चुकी है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे पदाधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए श्री कुमार का वित्तीय वर्ष 2016-17 की छात्रवृत्ति की राशि निर्गत करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

.....

संशोधित पेंशन का निर्धारण

56. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सरकार की नई पेंशन प्रणाली से सेवानिवृत्त शिक्षकों को आर्थिक घाटा हो रहा है ;

(ख) क्या यह सही है कि 4800 ग्रेड-पे के स्थान पर 5400 ग्रेड-पे करने की मांग शिक्षक संगठनों एवं पेंशन समाज के द्वारा की जाती रही है ;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कब तक पेंशन की पुरानी व्यवस्था लागू करते हुए सेवानिवृत्त शिक्षकों को 5400 ग्रेड-पे के आधार पर संशोधित पेंशन निर्धारण करने का आदेश देना चाहती है ?

उत्तर –

(क) अस्वीकारात्मक ।
प्रश्न स्पष्ट नहीं है। यदि प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि सरकार की नई पेंशन प्रणाली से सेवानिवृत्त शिक्षकों को आर्थिक घाटा हो रहा है तो वस्तुस्थिति यह है कि बिहार सरकार में दिनांक 1.9.2005 एवं उसके बाद नियुक्त सभी राज्यकर्मी नई पेंशन प्रणाली से आच्छादित हैं। एवं उसके प्रावधान के अनुरूप ही सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाने का प्रावधान है। सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए भी सभी राज्यकर्मियों के अनुरूप ही सुविधा देय है।

(ख) प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

(ग) उपरोक्त में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

.....

नलकूप ठीक कबतक

57. **श्री दिलीप कुमार जायसवाल** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के लगभग 75 प्रतिशत नलकूप खराब होने के कारण किसानों की सिंचाई प्रभावित हो रही है ;

(ख) क्या यह सही है कि नलकूप खराब रहने के कारण रबी एवं खरीफ फसल की सिंचाई समय पर नहीं होने के कारण किसानों का फसल का उत्पादन कम हो रहा है, जिसके कारण भुखमरी उत्पन्न हो रही है ;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार प्रदेश में बंद एवं खराब पड़े नलकूपों को कब तक ठीक कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

.....

रक्षात्मक कदम

58. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रूनी सैदपुर प्रखंड के लगभग पांच - छः पंचायतों में नीलगाय, जंगली सूअर एवं अन्य जंगली जानवरों का उत्पात है, जिससे किसानों के फसल की काफी बर्बादी होती है ;

(ख) यदि खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो फसल की बर्बादी न हो, इसके लिए सरकार कौन-सा रक्षात्मक कदम उठाना चाहती है ?

.....

कार्रवाई कबतक

59. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मोतिहारी प्रखण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय (ग्रामीण) द्वारा सेविका-सहायिका का चयन किया जाना था ;

(ख) क्या यह सही है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ग्रामीण पर्यवेक्षिका तथा लिपिक द्वारा सेक्टर 2, 3, 4, 5, 7 से संबंधित संचिकाओं की चोरी कर लिए जाने के संबंध में छतौनी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है ;

(ग) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बतलाएगी कि प्रखण्ड कार्यालय के आलमीरा से बिना तोड़े सिर्फ पांच सेक्टरों से संबंधित सेविका-सहायिका के चयन से संबंधित संचिका कैसे चोरी कर ली गई तथा अनुसंधान में पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गयी, विभाग के संलिप्त कर्मचारियों पर सरकार कोई कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उतर –

(क) स्वीकारात्मक है।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पत्रांक 575 दिनांक 4.2.19 जिसे प्रतिवेदित किया गया है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय, मोतिहारी ग्रामीण में सेविका/सहायिका चयन हेतु विज्ञापन संख्या 01/2018 प्रकाशित किया गया था।

(ख) स्वीकारात्मक है।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संचिका चोरी से संबंधित घटना के संबंध में छतौनी थाना में कांड संख्या 232/18 दिनांक 14.8.2018 दर्ज किया गया है।

(ग) उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

सेविका/सहायिका के चयन से संबंधित संचिका चोरी की घटना में संलिप्त कर्मियों एवं अन्य के विरूद्ध छतौनी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसका अनुसंधान पुलिस द्वारा किया जा रहा है। चोरी की घटना में संलिप्त कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

.....

बांध एवं पईन का निर्माण

60. **श्री संजीव श्याम सिंह** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि गया जिला के डुमरिया प्रखण्ड के नारायणपुर पंचायत के ग्राम-बाघपुर में मनिपहाड़ के नीचे बांध एवं पईन नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थान पर बांध एवं पईन नहीं रहने के कारण काफी दिक्कत होती है;

(ग) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त स्थान पर बांध एवं, पईन का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

.....

स्वचालित शौचालय

61. **श्रीमती रीना देवी** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में महिला आरक्षण लागू किये जाने के उपरांत काफी संख्या में महिला पुलिस की बहाली हुई है ;

(ख) क्या यह सही है कि सार्वजनिक स्थल पर शौचालय नहीं रहने की स्थिति में ड्यूटी में तैनात महिला पुलिस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है ;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार महिला पुलिस बल के लिए स्वचालित शौचालय की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

.....

बंदरों का उत्पात

62. **डॉ०रामवचन राय** : क्या मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के पटना सिटी इलाके में चौक गुरूद्वारा और मारूफगंज में बंदरों ने आतंक मचा रखा है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त इलाके में लगभग एक दर्जन लोगों को बंदर ने काट लिया है, जिससे वहां रह रहे लोगों में भय व्याप्त है ;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त इलाके के लोगों को बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलाना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

.....

ट्रैफिक पुलिस की बहाली

63. **श्री संजय प्रकाश** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राजधानी पटना में यातायात व्यवस्था हेतु 2400 ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता है जिसके बदले सिर्फ 1000 ट्रैफिक पुलिस हैं ;

(ख) यदि उपरोक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो राज्य सरकार बाकी बची 1400 ट्रैफिक पुलिस को कबतक बहाल करेगी ?

.....

लाभुकों को पेंशन राशि

64. **श्री टुनजी पाण्डेय** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सिवान जिले की विभिन्न पंचायतों से वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन का फार्म भरकर जिले को भेजा गया है ;

(ख) क्या यह सही है कि पिछले वित्तीय वर्ष में लाभुकों के नाम की अनुशंसा भी हुई है ;

(ग) क्या यह सही है कि अभी तक इन लोगों को पेंशन की राशि नहीं मिल रही है ;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लाभुकों को पेंशन की राशि देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

.....

अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति

65. **श्री संजय पासवान** : क्या मंत्री,गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति की महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास से संबंधित नरहट थाना कांड सं0 -26/2017 एवं अल्पवयस्क छात्रा का अश्लील विडियो बनाकर और उसे ब्लैकमेल करके शारीरिक शोषण करने के फलस्वरूप छात्रा की मौत से संबंधित नरहट थाना कांड सं0 145/17 के मुकदमा को वापस लेने तथा केस को रफा-दफा करने हेतु अपराधी तत्व नाजायज दबाव बना रहे हैं ;

(ख) क्या यह सही है कि नरहट थाना कांड सं0 316/18 एवं 318/18 के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीडित परिवारों की मदद करने वाले स्थानीय समाजसेवी श्री मसीहुद्दीन को अपराधी तत्वों ने दो बार धमकी दी है कि उपरोक्त मुकदमें रफा-दफा नहीं कराने पर उनकी तथा उनके परिजनों की हत्या कर दी जायेगी ;

(ग) क्या यह सही है कि स्थानीय पुलिस ने धमकी देने वाले कुख्यात अपराधकर्मी को गिरफ्तार करके उससे गहन पूछताछ की है तथा उसे जेल भेज दिया है ;

(घ) क्या यह सही है कि विशेष शाखा तथा स्थानीय पुलिस ने प्रतिवेदित किया है कि स्थानीय समाजसेवी श्री मसीहुउद्दीन का जीवन गंभीर खतरे में बना हुआ है तथा उनकी सुरक्षा की नितांत आवश्यकता है ;

(ङ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार समाजसेवी के सुरक्षार्थ अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति करना चाहती है यदि हां तो कबतक और नहीं तो क्यों ?

.....

बालू का अवैध खनन

66. **श्री मनोज यादव** : क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बालू खनन संवेदक को पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की बिना अनुमति के किसी भी घाट का बालू खनन कार्य नहीं किया जा सकता है ;

(ख) क्या यह सही है कि जितने स्थल से बालू का खनन किया जायेगा उस स्थल पर मिट्टी भराई एवं हरे-भरे वृक्षों का रोपन कार्य आवश्यक है ;

(ग) क्या यह सही है कि बांका जिले में घाटों के मापी नहीं रहने के कारण पर्यावरण विभाग की सहमति प्राप्त घाटों से खनन कार्य न होकर इसी सहमति की आड़ में दूसरे अन्य घाटों का खनन कार्य किया जा रहा है ;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इस तरह के अवैध बालू खनन कार्य करने वाले संवेदक पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

.....

फसल बीमा की राशि

67. **श्री देवेश चन्द्र ठाकुर** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2017 के अगस्त माह में सीतामढ़ी जिला में भयंकर बाढ़ आयी थी जिसमें चोरौत प्रखंड के किसानों की फसल पूरी तरह बरबाद हो गयी थी, जिसमें सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित किसानों को फसल क्षति हेतु कृषि इनपुट की राशि वितरित की गई थी ;

(ख) क्या यह सही है कि चोरौत प्रखंड किसान क्रेडिट कार्डधारक किसानों को फसल क्षति के बावजूद कृषि इनपुट की राशि नहीं दी गयी थी और कहा गया था कि आपको बैंक की ओर से फसल बीमा का लाभ दिया जायेगा ;

(ग) क्या यह सही है कि अब वैसे बाढ़ प्रभावित कृषकों को फसल क्षति /फसल बीमा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि बाढ़ अनुश्रवण समिति की रिपोर्ट में भी औसतन चोरौत प्रखंड में 80-90% फसल क्षति तय पायी गयी थी ;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चोरौत प्रखंड किसान क्रेडिट कार्डधारी कृषकों को भी फसल क्षति के अनुरूप ही कृषि इनपुट/अन्य वित्तीय सहायता तथा फसल बीमा की राशि देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

.....

बाइकर्स गैंग पर अंकुश

68. **श्री राम चन्द्र पूर्वे** : क्या मंत्री,गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य की राजधानी पटना में दर्जन भर से अधिक बाइकर्स गैंग का गठन हो चुका है;

(ख) क्या यह सही है कि इन गैंग के द्वारा पटना के कई स्थानों पर बंद घरों में बाइक चेन लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जिस कारण शहर के आम नागरिकों में काफी दहशत है ;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त गैंग में मैट्रिक से स्नातक पास छात्र काफी संख्या में सम्मलित हो रहे हैं, जो परिवार एवं समाज के लिए चिन्ता का विषय है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो इस तरह के गैंग के गठन का क्या कारण है, और इसकी रोकथाम के लिए सरकार कौन-सा उपाय कर रही है?

.....

अनुशासनिक कार्रवाई

69. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि आई. टी. आई. परीक्षा वर्ष 2019 में केन्द्राधीक्षकों के रूप में गैर तकनीकी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया था ;

(ख) क्या यह सही है कि इन गैर तकनीकी पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के कारण परीक्षा संचालन में काफी कठिनाई हुई एवं विभिन्न केन्द्रों पर परीक्षा स्थगित करनी पड़ी ;

(ग) क्या यह सही है कि गैर अनुभव वाले इन पदाधिकारियों पर तत्समय हुईं गड़बडियों के लिए अनुशासनिक कारवाई की जा रही है ;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भविष्य में इन पदाधिकारियों को ऐसे कार्यों और उनको अनुशासनिक कार्रवाई से मुक्त करना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

.....

स्थायी पुलिस कैम्प

70. **श्री संतोष कुमार सुमन** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि खगडिया जिला के मोरकाही थाना अन्तर्गत छमसिया कामाथान सारो, बेतहा, बोचघसका गांव अति दुर्गम तीन नदियों से घिरा हुआ इलाका है ;

(ख) इस इलाके में कई आपराधिक गिरोह एवं माओवादी संगठन सक्रिय हैं ;

(ग) विगत वर्षों में छमसिया गांव में अस्सी मुसहर जाति के घरों में अपराधियों द्वारा आगजनी की गई। इस बाबत मोरकाही थाना काण्ड संख्या-161/2017 दर्ज हुआ है, जिससे राज्य सरकार की बदनामी देश स्तर पर हुई है ;

(घ) आगजनी की सुविधा को देखते हुए खगड़िया जिला के मोरकाही थानान्तर्गत छमसिया गांव में स्थायी पुलिस कैम्प (ओ.पी.) स्वीकृत करने की आवश्यकता है ;

(ङ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार छमसिया गांव में स्थायी पुलिस कैम्प (ओ.पी.) स्वीकृत करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

.....

पटना

दिनांक 14 फरवरी, 2019

विनोद कुमार
कार्यकारी सचिव
बिहार विधान परिषद्